कृषि तकनीकों का विकास

2446. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस शताब्दी के अन्त तक खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में लगभग 240 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न के उत्पादन की प्राप्ति हेतु कृषि के वर्तमान तकनीकों को विकसित करने की अत्यावश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस देश की आवश्यकता और इसके पर्यावरण के अनुसार तकनीकों को विकसित करने में कोई प्रगति की है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्राम किसानों को ये तकनीकें उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान के एक नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा दे रही है । इसके अंतर्गत अनुसंधान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनायें, तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनायें और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनायें और सहयोगी के रूप में राज्य कृषि विश्वविद्यालय आते हैं । विभिन्न खाद्य फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की गई हैं और संकर अनुसंधान, प्रजनक बीज के उत्पादन, जर्म-प्लाज्म के संरक्षण, जैविक और अजैविक दबाव रोधी सुधरी किस्मों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों, राष्ट्रीय प्रदर्शनों, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं और प्रयोगशालाओं से खेत तक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को विकसित की गई टेक्नोलोजी उपलब्ध कराई जा रही है।

सहकारी भंडारण परियोजनाओं को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता

2447. श्री कमीज जोषी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी भण्डागारण परियोजनाओं को राज्य वार कितनी-कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग राज्यों में कितने-कितने भंडागारों का निर्माण किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अधीन कितने भांडागारों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अधीन कितने गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

कृषि विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुस्ता-पल्लीराजबन्धम) : : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय परियोजना के अधीन बिहार सरकार को 642.109 लाख रुपये की राशि प्रदान की है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	दी गई राशि
1989-90 . . .	170.90
1990-91 . . .	273.29
1991-92 . . .	197.90
योग :	642.090

पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त भण्डारण परियोजना के अधीन कोई दूसरा राज्य शामिल नहीं है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, परियोजना के अधीन बिहार में 169 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है जिनका ब्यौरा निम्नांकित है :—

वर्ष	निर्मित गोदाम संख्या
1989–90	शून्य
1990–91	27
1991–92	142
योग :	169

(ग) इस परियोजना के अधीन चालू वर्ष अर्थात् 1992–93 के दौरान बिहार में 321 ग्रामीण गोदाम निर्मित करने का प्रस्ताव है ।

Supply of Liquid Milk at Cheaper Rates

2448. SHRI SATYA PRAKASH MALAVAIYA :
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is the Policy of the Government of India to ensure availability of liquid milk at a cheaper price for metropolitan cities like Delhi and Calcutta ;

(b) if so, whether Government have ever taken steps to restrict the movements of liquid milk on state basis or any region basis ;

(c) whether Government have also tried to restrict the production of milk products such as milk powder, ghee, butter, cheese and milk chocolates ;and

(d) what are the details of such measures taken during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K.C. LENKA) : (a) Government assigns priority to increase the availability of liquid milk of good quality to the general public at reasonable price, particularly during the lean season and in milk deficit areas .

(b) and (c) In order to augment availability of liquid milk during the lean season temporary restrictions have been imposed in some States/Union Territories for a limited period for manufacture of certain milk products and also export of milk outside the States/Union Territories.

(d) A Statement indicating the details of the Orders promulgated by the State Governments/Union Territories during the last three years is enclosed.

Statement

Sl. No.	Name of the Control Order	Period		
		1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1	Delhi (Milk & Milk Foods) Control Order	12-6-89 to 15-8-89	..	1-5-91 and withdrawn 26-12-91
2	Madhya Pradesh (Manufacture of Milk Products from Milk and Export) Control order	..	..	27-6-91 to 15-8-91